

एम./एस. यशवंत ग्रामिन शिक्षण संस्था

बनाम

सहायक प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और अन्य

(सिविल अपील संख्या 721/2013)

09 मार्च, 2017

[दीपक मिश्रा, ए. एम. खानविलकर और मोहन एम. शांतनगौदर, जेजे.]

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952-धारा 16-की प्रासंगिकता-अपीलकर्ता एक पंजीकृत सोसायटी है और स्कूल और कॉलेज चलाता है-इसने राज्य सरकार के अनुमोदन से अंशकालिक कर्मचारियों की नियुक्ति की-क्या 1952 अधिनियम (केंद्रीय अधिनियम) के प्रावधान अपीलार्थी के स्कूलों/कॉलेजों में अंशकालिक कर्मचारियों पर लागू होंगे, जिनकी सेवा की शर्तें राज्य अधिनियम और राज्य नियमों के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती हैं और क्या अपीलार्थी को अपने 16 अंशकालिक कर्मचारियों के भविष्य निधि योगदान को जमा करने में चूक माना जाता है-अभिनिर्धारित किया: अपीलार्थी 100% अनुदान सहायता स्कूल है और राज्य सरकार के नियंत्रण में है-अपीलार्थी के स्कूल/कॉलेज में काम करने वाले कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा बनाई गई अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा पात्रता के अधीन आते हैं-अपीलार्थी-समिति, इस प्रकार,

धारा 16 (1) (बी) में निर्दिष्ट दोहरी शर्तों को पूरा करती है-यह इस प्रकार है कि इसे केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों के आवेदन से छूट दी गई है-एक बार जब कोई प्रतिष्ठान केंद्रीय अधिनियम की धारा 16 के तहत किसी एक अपवादात्मक श्रेणी के तहत आता है, तो केंद्रीय अधिनियम द्वारा सशक्त अधिकारियों को ऐसे प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं होगा; और इससे भी अधिक इस आधार पर कि प्रतिष्ठान में काम करने वाले कर्मचारियों (16 अंशकालिक कर्मचारी) की एक छोटी संख्या बाकी नियमित कर्मचारियों को नियंत्रित करने वाली राज्य अंशदायी भविष्य निधि योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं थी। अपीलार्थी की स्थापना के खिलाफ वसूली की कार्रवाई की शुरुआत, जिसे अन्यथा केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों के आवेदन से छूट दी गई थी, इसलिए, पूरी तरह से कानून के अधिकार के बिना है-महाराष्ट्र निजी स्कूलों के कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम, 1981-आर 20-महाराष्ट्र निजी स्कूलों के कर्मचारी (सेवा की शर्तें) विनियमन अधिनियम, 1977।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (केंद्रीय अधिनियम) की धारा 1 के सरल अध्ययन से पता चलता है कि केंद्रीय अधिनियम उसमें निर्दिष्ट प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। तत्काल मामले में, अपीलार्थी का प्रतिष्ठान धारा 1 (3) के उपखंड (बी) में निर्दिष्ट

"अन्य प्रतिष्ठान" के दायरे में आ सकता है। यह निर्विवाद है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (3) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एक अधिसूचना प्रकाशित की है जिसमें सभी शैक्षणिक संस्थानों को "किसी अन्य प्रतिष्ठान" की श्रेणी में शामिल किया गया है, जैसे कि विश्वविद्यालय; महाविद्यालय (चाहे वह विश्वविद्यालय से संबद्ध हो या न हो); विद्यालय (चाहे वह केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो या सहायता प्राप्त हो); कोई भी वैज्ञानिक संस्थान; कोई भी संस्थान जिसमें किसी भी मामले के संबंध में शोध किया जाता है; और कोई भी अन्य संस्थान जिसमें ज्ञान या प्रशिक्षण प्रदान करने की गतिविधि व्यवस्थित रूप से की जाती है। उक्त अधिसूचना के साथ केंद्रीय अधिनियम की धारा 1 के संयुक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि केंद्रीय अधिनियम उस अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के अधीन सभी कॉलेजों और स्कूलों पर लागू होगा। [पैरा 16,17) (952-डी-जी]

2.1 तब सवाल उठा: क्या अपीलकर्ता स्कूल केंद्रीय अधिनियम की धारा 16 में निर्दिष्ट किसी भी अपवादात्मक श्रेणी के अंतर्गत आने वाला एक प्रतिष्ठान है। अपीलार्थी ने केंद्रीय अधिनियम की धारा 16 (1) के खंड (ए) के साथ-साथ खंड (बी) को लागू किया है। जहां तक खंड (ए) पर आधारित तर्क का संबंध है, यह इस आधार पर आगे बढ़ता है कि अपीलार्थी के स्कूल (जिसमें 16 अंशकालिक कर्मचारी काम कर रहे थे) ने

पचास से कम व्यक्तियों को नियुक्त किया था और बिना शक्ति की सहायता के काम कर रहा था। यह तर्क अपीलार्थी की सहायता के लिए नहीं आ सकता। चूंकि, अपीलार्थी 29 स्कूल/कॉलेज चला रहा है और उसने लगभग 1151 स्थायी कर्मचारियों को नियुक्त किया है। केंद्रीय अधिनियम की धारा 2 ए भविष्यवाणी करती है कि जहां किसी प्रतिष्ठान में अलग-अलग विभाग होते हैं या उनकी शाखाएं होती हैं, चाहे वे एक ही स्थान पर स्थित हों या अलग-अलग स्थानों पर, ऐसे सभी विभागों या शाखाओं को एक ही प्रतिष्ठान का हिस्सा माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, यह तथ्य कि अपीलार्थी ने 50 से कम स्थायी कर्मचारियों को नियुक्त किया है और जो उस स्कूल में पावर की सहायता के बिना काम कर रहे हैं जिसमें 16 अंशकालिक कर्मचारी भी काम कर रहे थे, इस मामले को आगे नहीं ले जाएगा। अपीलार्थी ने न तो भौतिक तथ्यों का अनुरोध किया है और न ही कोई सबूत पेश किया है, ताकि केंद्रीय अधिनियम की धारा 2 ए में निर्धारित इस धारणा का खंडन किया जा सके कि अपीलार्थी द्वारा संचालित सभी स्कूल और कॉलेज एक ही प्रतिष्ठान का हिस्सा थे। यह तथ्य कि अपीलार्थी स्वयं राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति है, अपीलार्थी को केंद्रीय अधिनियम के आवेदन से मुक्त नहीं करेगा। [पैरा 18] (952-जी-एच; 953-ए-डी)

2.2 धारा 16 (1) का उपखंड (बी) एक स्वतंत्र अपवादात्मक श्रेणी है। यह केंद्र सरकार या राज्य सरकार से संबंधित या उसके नियंत्रण वाले किसी भी अन्य प्रतिष्ठान की ओर आकर्षित होता है और जिसके कर्मचारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाई गई किसी भी योजना या नियम के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि या वृद्धावस्था पेंशन के लाभों के हकदार हैं। केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों से छूट की मांग करने वाले संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा इन दो शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी के संबंधित स्कूलों/कॉलेजों में काम करने वाले कर्मचारी पात्रता के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाई गई अंशदायी भविष्य निधि योजना के दायरे में आते हैं। इस प्रकार केंद्रीय अधिनियम के तहत छूट प्राप्त करने के लिए आवश्यक दूसरी शर्त पूरी हो जाती है। सवाल यह है कि जिन स्कूलों में 16 अंशकालिक कर्मचारी काम कर रहे थे, क्या उन्हें केंद्र सरकार या राज्य सरकार से संबंधित या उसके नियंत्रण में एक प्रतिष्ठान कहा जा सकता है। [पैरा 19,20] (953-ई-एच; 954-ए)

2.3 सवाल यह है कि क्या विषय राज्य अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में समान प्रावधान हैं ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि राज्य सरकार अपीलार्थी जैसे प्रतिष्ठानों पर पर्याप्त नियंत्रण रखती है। राज्य अधिनियम, उसके तहत बनाए गए नियम और माध्यमिक विद्यालय संहिता के प्रावधान शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में अपने आप में

एक पूर्ण संहिता हैं और ऐसे संस्थानों पर राज्य सरकार द्वारा ठोस नियंत्रण के प्रयोग की सीमा का संकेत देते हैं, चाहे वे उसके स्वामित्व में हों। राज्य सरकार के पास शिक्षण संस्थानों के कामकाज को निर्देशित करने, प्रतिबंधित करने या विनियमित करने की अधीक्षण और अधिकार है। यह अनिवार्य रूप से इस बात का अनुसरण करता है कि अपीलार्थी की स्थापना, जो इस मामले में अनुदान सहायता स्कूल है जिसमें 16 अंशकालिक कर्मचारी काम कर रहे थे, राज्य सरकार के नियंत्रण में है और इस प्रकार केंद्रीय अधिनियम की धारा 16 (1) (बी) की पहली शर्त को भी पूरा करेगा। [पैरा 21,22) (956-जी. एच.; 959-ए. सी.]

2.4 चूंकि यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपीलार्थी की स्थापना धारा 16 (1) (बी) में निर्दिष्ट जुड़वां शर्तों को पूरा करती है, इसलिए इसे केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने से छूट दी जानी चाहिए। केंद्रीय अधिनियम की धारा 16 यह स्पष्ट करती है कि केंद्रीय अधिनियम के प्रावधान प्रतिष्ठान पर लागू नहीं होंगे, यदि वे उसमें प्रदान की गई अपवादात्मक श्रेणी में से किसी एक के अंतर्गत आते हैं। यह छूट समग्र रूप से प्रतिष्ठान के लिए और सभी उद्देश्यों के लिए केंद्रीय अधिनियम के लागू होने से है। एक बार जब प्रतिष्ठान को छूट प्राप्त करने के लिए धारा 16 में निर्दिष्ट बहिष्कृत श्रेणी द्वारा कवर किया जाता है, तो यह समझ से परे है कि केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों को ऐसे प्रतिष्ठान के खिलाफ

इस तर्क पर लागू किया जा सकता है कि कुछ (इस मामले में 16) अंशकालिक कर्मचारी राज्य सरकार की सी. पी. एफ. योजना के दायरे में नहीं थे, जैसा कि इसके बाकी कर्मचारियों पर लागू होता है। (पैरा 23) (959-सी, एफ-एच)

3. एक बार जब प्रतिष्ठान केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों के आवेदन की छूट के लिए अर्हता प्राप्त कर लेता है, तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि केंद्रीय अधिनियम के तहत अधिकारी उस पर अधिकार का प्रयोग कर सकें या प्रतिष्ठान को केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए कह सकें, जब तक कि प्रतिष्ठान की छूट को वापस नहीं लिया जाता है या न्यायिक रूप से हटा नहीं दिया जाता है। केंद्रीय अधिनियम की धारा 16 में कर्मचारियों के संबंध में केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की आंशिक छूट की अवधारणा की परिकल्पना नहीं की गई है, लेकिन यह छूट सभी उद्देश्यों के लिए प्रतिष्ठान को संचालित करती है। तत्काल मामले में, अपीलकर्ता 29 स्कूल/कॉलेज चला रहा है और 28 स्कूलों/कॉलेजों के संबंध में राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहा है। अपीलार्थी के उक्त विद्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को राज्य सरकार की अनुमति और अनुमोदन से नियुक्त किया गया है और वे राज्य सी. पी. एफ. योजना द्वारा शासित हैं। राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया की सख्ती से निगरानी की गई है। इसके

अतिरिक्त, अपीलकर्ता अपने कर्मचारियों के वेतन बिल शिक्षा विभाग को जमा कर रहा है जो सीधे वेतन जमा करता है। ऐसे कर्मचारियों को उनके बैंक खातों में जमा करना। प्रासंगिक समय पर, अपीलार्थी ने लगभग 1151 कर्मचारियों को नियुक्त किया था जो निजी स्कूलों के कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाई गई अंशदायी भविष्य निधि योजना के दायरे में थे (16 अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर जो पूर्णकालिक काम नहीं कर रहे थे)। अपीलार्थी ने राज्य सरकार की अनुमति और अनुमोदन से उन 16 अंशकालिक कर्मचारियों को नियुक्त किया था। यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि राज्य सरकार इस तथ्य से पूरी तरह से अवगत थी कि वे अंशकालिक कर्मचारी राज्य की सी. पी. एफ. योजना के लाभों के हकदार नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में, अपीलार्थी के कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या, यदि उनमें से सभी नहीं हैं, तो लगभग 1151 कर्मचारी, राज्य अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित निजी स्कूलों पर लागू राज्य सरकार की अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा कवर किए गए थे। सिर्फ इसलिए कि अपीलार्थी के स्कूल में काम करने वाले 16 अंशकालिक कर्मचारी राज्य सी. पी. एफ. योजना के लाभों के लिए पात्र नहीं थे, केंद्रीय अधिनियम की धारा 16 के तहत अधिग्रहित अपीलार्थी की स्थापना की छूट की स्थिति बंद नहीं होगी या स्वचालित रूप से वापस नहीं ली जाएगी। (पैरा 24,25) (960-बी-एच; 961-ए)

4. एक बार जब कोई प्रतिष्ठान केंद्रीय अधिनियम की धारा 16 के तहत किसी भी अपवाद श्रेणी के तहत आता है, तो केंद्रीय अधिनियम द्वारा सक्षम अधिकारियों को ऐसे प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं होगा; और विशेष रूप से इस आधार पर कि प्रतिष्ठान में काम करने वाले कर्मचारियों (16 अंशकालिक कर्मचारी) की एक छोटी संख्या प्रतिष्ठान के बाकी नियमित कर्मचारियों को नियंत्रित करने वाली राज्य अंशदायी भविष्य निधि योजना के तहत लाभों के लिए पात्र नहीं थी। अपीलार्थी की स्थापना के खिलाफ प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधिकारी (यों) द्वारा वसूली की कार्रवाई शुरू करना, जिसे अन्यथा केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने से छूट दी गई थी, पूरी तरह से कानून के अधिकार के बिना है। [पैरा 26,27] (961-बी-डी)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बनाम सनातन धर्म बालिका माध्यमिक विद्यालय और अन्य (2007) 1 एस. सी. सी. 268: [2006] 7 पूरक एससीआर 849-पर भरोसा किया गया।

शामराव विट्ठल सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम कासरगोड पांडुरंग माल्या (1972) 4 एस. सी. सी. 600: (1972) 2 एस. सी. आर. 162-निर्दिष्ट।

प्रकरण विधि संदर्भ

[2006) 7 पूरक एस. सी. आर. 849 भरोसा किया पैरा 20

[1972] 2 एस. सी. आर. 162 संदर्भित पैरा 27

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 721/2013

2011 की रिट याचिका संख्या 4013 में बॉम्बे उच्च न्यायालय नागपुर की पीठ के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 17.01.2012 से।

सत्यजीत देसाई, सुश्री अनघा एस. देसाई, नीलमणि पंत, अपीलार्थी के वकील।

कुणाल ए. चीमा, अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता, योगेश के. अहिरराव, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, विजय प्रकाश, पी. सोमा सुंदरम, प्रत्यर्थियों के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय ए. एम. खानविलकर, जे. द्वारा दिया गया

1. वर्तमान सिविल अपील बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ द्वारा दिनांक 17 जनवरी, 2012 को 2011 की रिट याचिका संख्या 4013 में पारित निर्णय और अंतिम आदेश से उत्पन्न होती है। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर उपरोक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षिप्त 'न्यायाधिकरण' के लिए) दिनांक 8 अप्रैल, 2011 के आदेश की आलोचना

की गई थी, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अपीलार्थी को अपने अंशकालिक कर्मचारियों में से 16 (सोलह) के भविष्य निधि योगदान को जमा करने में चूक माना गया है।

2. कानूनी प्रस्तुतियों और मुद्दों से निपटने से पहले, वर्तमान अपील दायर करने के लिए तथ्यात्मक मैट्रिक्स निर्धारित करना उचित होगा:

क) अपीलार्थी सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 और बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है और वर्धा जिले, नागपुर में 29 (उनतीस) स्कूल और जूनियर कॉलेज चलाता है। जिनमें से 28 (अट्ठाईस) स्कूलों और कॉलेजों को कथित तौर पर राज्य सरकार से 100% अनुदान प्राप्त हुआ।

ख) 1996 और 1997 के बीच, प्रशासनिक अनिवार्यता के कारण राज्य सरकार की अनुमति/अनुमोदन से अपीलार्थी के कुछ कॉलेजों में 16 अंशकालिक लाइब्रेरियन नियुक्त किए गए थे। ये पुस्तकालयाध्यक्ष नियमित पूर्णकालिक कर्मचारियों द्वारा लगाए गए कार्य घंटों के विपरीत कम घंटों के लिए काम करते थे। अपीलार्थी का तर्क है कि नियुक्ति और अनुमोदन की पूरी प्रक्रिया की निगरानी और पर्यवेक्षण राज्य सरकार द्वारा किया गया था। इसके अलावा, अपीलार्थी का अपने कर्मचारियों के वेतन के भुगतान या कटौती पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं था। यह राज्य प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है।

ग) 5 मई, 1998 को, अपीलार्थी ने भविष्य निधि में कटौती करने के अनुरोध के साथ शिक्षा अधिकारी को अंशकालिक पुस्तकालयाध्यक्षों में से एक का बिल भेजा। इस अनुरोध को 19 नवंबर, 1998 के एक पत्र के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया था, जिसमें ऐसे अंशकालिक कर्मचारियों के भविष्य निधि योगदान में कटौती नहीं करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद 5 मार्च, 2004 को शिक्षा निदेशक ने एक पत्र जारी कर स्पष्ट किया कि अंशदायी भविष्य निधि योजना ऐसे अंशकालिक कर्मचारियों पर लागू नहीं होती है। उपरोक्त संचारों को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी के पास यह मानने का कारण था कि उसे अपने 16 अंशकालिक कर्मचारियों के भविष्य निधि योगदान में कटौती और/या जमा करने की आवश्यकता नहीं थी।

घ) 6 अक्टूबर, 2005 को प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधिकारियों ने अपीलार्थी के एक स्कूल का दौरा किया और कर्मचारियों और भविष्य निधि योगदान के संबंध में उनकी ओर से किए गए भुगतान का विवरण मांगा।

ङ) अपीलार्थी ने 18 अक्टूबर, 2005 के अपने पत्र के माध्यम से उपरोक्त प्रश्न का अपना जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलार्थी ने उल्लेख किया कि कानून के अनुसार, संबंधित अंशकालिक कर्मचारियों के भविष्य निधि योगदान में कटौती करने की आवश्यकता नहीं थी।

च) हालाँकि, अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या एक से अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि बकाया का भुगतान करने में विफलता के संबंध में पेश होने के लिए 23 मई, 2006 दिनांकित समन प्राप्त हुआ। उस संबंध में पक्षकारों के बीच आगे पत्राचार हुआ और मामले में स्थगन लिया गया।

छ) अंततः, प्रतिवादी संख्या 1 ने मामले की सुनवाई की और 1 अगस्त, 2007 को एक आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि अपीलकर्ता 16,89,796 रुपये बकाया भविष्य निधि योगदान के रूप में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

ज) अपीलार्थी ने तब उपरोक्त आदेश के खिलाफ 14 सितंबर, 2007 को एक समीक्षा आवेदन दायर किया, इस आधार पर कि प्रतिवादी संख्या 1 सुनवाई के समय उठाए गए कुछ सामग्री प्रस्तुतियों और आपत्तियों की सराहना करने में विफल रहा था। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने सुनवाई किए बिना एक पृष्ठ के आदेश के साथ उक्त समीक्षा को खारिज कर दिया।

झ) उपर्युक्त कार्यवाही के दौरान, अपीलार्थी के 16 अंशकालिक पुस्तकालयाध्यक्षों में से 3 (तीन) को 29 सितंबर, 2007 से नियमित कर दिया गया था। एक अन्य लाइब्रेरियन को 29 सितंबर, 2009 को नियमित किया गया था। यह राज्य प्राधिकरणों की मंजूरी से किया गया था।

ट) प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा पारित उपरोक्त आदेश से पीड़ित, अपीलार्थी ने अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष एक अपील दायर की, जिसने 8 अप्रैल, 2011 के अपने आदेश के माध्यम से अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि पूर्णकालिक और अंशकालिक कर्मचारियों के बीच कोई अंतर नहीं था और इस प्रकार अपीलार्थी अंशकालिक कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि योगदान में कटौती/भुगतान करने के लिए बाध्य था।

ठ) प्रतिवादी संख्या 1 ने इसके बाद 25 मई, 2011 तक देय राशि के भुगतान के लिए अपीलार्थी के स्कूलों में से एक को 10 मई, 2011 को एक मांग नोटिस जारी किया। इसके बाद 23 जून, 2011 को प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा गिरफ्तारी का वारंट क्यों जारी नहीं किया जाए, इसके बारे में कारण दर्शाएँ नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी ने 8 जुलाई, 2007 के अपने पत्र के माध्यम से कथित कारणदर्शक नोटिस का जवाब दिया, जिसमें मांग के अनुसार राशि का भुगतान करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा गया था।

ड) इस बीच, अपीलार्थी ने अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित 8 अप्रैल, 2011 के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष 2011 की रिट याचिका No.4013 भी दायर की। उच्च न्यायालय ने आदेश

पर रोक लगा दी और अपीलार्थी को अदालत में 4 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया, जिसका उसने विधिवत पालन किया।

द) अंततः, 17 जनवरी, 2012 को, उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया।

3. उपरोक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स के आलोक में, वर्तमान अपील महाराष्ट्र निजी स्कूलों के कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम, 1981 के नियम 20 की व्याख्या का सवाल उठाती है, जैसा कि महाराष्ट्र निजी स्कूलों के कर्मचारी (सेवा की शर्तें) विनियमन अधिनियम, 1977 (संक्षेप में क्रमशः 'राज्य नियम' और 'राज्य अधिनियम') के तहत बनाया गया है; साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (संक्षेप में 'केंद्रीय अधिनियम') की धारा 16 की भी व्याख्या का सवाल उठाती है। प्राथमिक मुद्दा यह है: क्या वर्तमान मामले में, केंद्रीय अधिनियम के प्रावधान अपीलार्थी के स्कूलों/कॉलेजों में अंशकालिक कर्मचारियों पर लागू होंगे, जिनकी सेवा की शर्तें राज्य अधिनियम और राज्य नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होती हैं। प्रासंगिक प्रावधानों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

केंद्रीय अधिनियम की धारा 16 इस प्रकार है:

"(1) यह अधिनियम लागू नहीं होगा-

(क) सहकारी समिति अधिनियम, 1912 (1912 का 2) के तहत पंजीकृत किसी भी प्रतिष्ठान पर, या सहकारी समितियों से संबंधित किसी भी राज्य में उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत, जिसमें पचास से कम व्यक्ति कार्यरत हैं और बिना पावर की सहायता के काम कर रहे हैं; या

(ख) केंद्र सरकार या राज्य सरकार से संबंधित या उसके नियंत्रण में किसी अन्य प्रतिष्ठान पर और जिसके कर्मचारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाई गई किसी योजना या नियम के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि या वृद्धावस्था पेंशन का लाभ पाने के हकदार हैं; या

(ग) किसी भी केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम के तहत स्थापित किसी अन्य प्रतिष्ठान को और जिसके कर्मचारी ऐसे लाभों को नियंत्रित करने वाले उस अधिनियम के तहत बनाई गई किसी योजना या नियम के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि या वृद्धावस्था पेंशन के लाभों के हकदार हैं;

(2) यदि केंद्र सरकार की राय है कि किसी भी वर्ग की वित्तीय स्थिति या मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन, जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जा सकती हैं,

उस वर्ग को अधिसूचना में निर्दिष्ट की गई अवधि के लिए इस अधिनियम के संचालन से छूट दे सकती है।

राज्य नियमों की धारा 20 इस प्रकार है:

"20. भविष्य निधि

(1) पूर्णकालिक आधार पर काम करने वाले सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी (जिसने पेंशन का विकल्प नहीं चुना है) या एक ही प्रबंधन द्वारा संचालित एक से अधिक विद्यालयों में अंशकालिक आधार पर कार्यरत और इन विद्यालयों में पूर्णकालिक काम करने वाला प्रत्येक कर्मचारी, समय-समय पर लागू अंशदायी भविष्य निधि नियम (बॉम्बे) के तहत अंशदायी भविष्य निधि की सदस्यता लेगा।

(2) पूर्णकालिक आधार पर काम करने वाले सहायता प्राप्त निजी माध्यमिक विद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी जिसे 1 अप्रैल 1966 से पहले नियुक्त किया गया था और जिसने अंशदायी भविष्य निधि योजना के लिए अपने विकल्प का लिखित रूप में उपयोग किया था, वह सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार उस निधि की सदस्यता लेगा और इस संबंध में लागू होगा।

4. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सत्यजीत देसाई पहले प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी के स्कूल राज्य सरकार से

अनुदान सहायता प्राप्त कर रहे हैं। अपीलार्थी 100% अनुदान सहायता प्राप्त करता है और उसके पास आय का कोई अलग स्रोत नहीं है। इसके अलावा, 16 अंशकालिक कर्मचारियों को राज्य सरकार की अनुमति और अनुमोदन से नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी का अपने कर्मचारियों के वेतन के भुगतान और कटौती पर भी सीधा नियंत्रण नहीं होता है। वास्तव में, संबंधित कर्मचारियों का वेतन भी सीधे राज्य शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है और उनके संबंधित बैंक खातों में जमा किया जाता है।

5. श्री देसाई तब प्रस्तुत करते हैं कि केंद्रीय अधिनियम की धारा 16 (1) (बी) के संदर्भ में, उक्त अधिनियम का उस प्रतिष्ठान पर कोई अनुप्रयोग नहीं है जो अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकार के नियंत्रण में है, जो स्पष्ट रूप से ऊपर प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी के स्कूल राज्य अधिनियम (और, विस्तार से, राज्य नियम) द्वारा शासित होते हैं जो एक विशेष कानून होने के कारण केंद्रीय अधिनियम को ओवरराइड करता है। इसके अलावा, अपीलकर्ता जिसने अंशकालिक कर्मचारियों को नियुक्त किया था, वह राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत एक प्रतिष्ठान है। जिन विद्यालयों में अंशकालिक कर्मचारी कार्यरत थे, उन्होंने 50 (पचास) से कम व्यक्तियों को नियुक्त किया है जो पावर की सहायता के बिना काम कर रहे थे। नतीजतन, केंद्रीय अधिनियम उस अधिनियम की धारा 16 (1) (ए) के संदर्भ में भी ऐसे प्रतिष्ठान पर लागू नहीं होता है।

6. कर्मचारियों की स्थिति के संबंध में, श्री देसाई प्रस्तुत करते हैं कि चाहे अपीलार्थी के कर्मचारी पूर्णकालिक हों या अंशकालिक, राज्य नियमों के नियम 20 में निर्धारित भविष्य निधि के लिए पात्र होने के लिए, उन्हें पूर्णकालिक भार कार्य करना होगा। वर्तमान मामले में, 16 अंशकालिक कर्मचारियों को सप्ताह में केवल लगभग 18 घंटे काम सौंपा गया था। पूर्णकालिक या नियमित कर्मचारियों के लिए प्रति सप्ताह 30 घंटे के सामान्य काम के बोझ की तुलना में सुबह 10:30 से दोपहर 2 बजे तक। दूसरे शब्दों में, वे पूर्णकालिक काम का बोझ नहीं उठा रहे थे और इस प्रकार राज्य अधिनियम के तहत संचालित भविष्य निधि योजना के दायरे में नहीं आते थे। नतीजतन, अंशकालिक कर्मचारी राज्य द्वारा बनाई गई भविष्य निधि योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।

7. श्री देसाई ने तब प्रस्तुत किया कि 3 अगस्त, 2006 के राज्य सरकार के प्रस्ताव में निर्देश दिया गया है कि अपीलकर्ता जैसे निजी स्कूलों में 5 (पाँच) वर्ष पूरे करने वाले सभी अंशकालिक लाइब्रेरियन को उन्नत किया जाए और पूर्णकालिक कर्मचारी बनाया जाए। इसे 30 मार्च, 2007 के शिक्षा अधिकारी के पत्र द्वारा दोहराया गया था, जिसमें अपीलार्थी को उपरोक्त प्रस्ताव को लागू करने का निर्देश दिया गया था। यह तथ्य कि अब पूर्णकालिक कर्मचारियों को नियमित होने के कारण भविष्य निधि लाभ दिए गए थे, यह स्वयं दर्शाता है कि अंशकालिक कर्मचारी भविष्य निधि

लाभों के हकदार नहीं थे। इसलिए राज्य सरकार ने भविष्य निधि कर्मचारियों के योगदान के लिए उनके वेतन से कोई कटौती नहीं की।

8. उपरोक्त किसी भी तर्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, श्री देसाई ने यह भी प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता हमेशा अपने अंशकालिक कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि योगदान में कटौती करने के लिए तैयार था और उसने इस बारे में संबंधित प्राधिकारी को भी लिखा था, लेकिन शिक्षा अधिकारी (मध्य) जिला परिषद, वर्धा द्वारा 19 नवंबर, 1998 के अपने पत्र के माध्यम से ऐसा करने से बचने के लिए स्पष्ट रूप से कहा गया था।

9. उत्तर में, प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री विजय प्रकाश प्रस्तुत करते हैं कि राज्य अधिनियम और राज्य नियमों के प्रावधानों के तहत अंशदायी भविष्य निधि (सी. पी. एफ.) की योजना अपीलार्थी के अंशकालिक कर्मचारियों पर लागू नहीं होती है। बल्कि, यह केंद्रीय अधिनियम के तहत बनाई गई कर्मचारी भविष्य निधि (ई. पी. एफ.) योजना है जो लागू होती है। श्री प्रकाश ने पहले अपने तर्क का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्रीय अधिनियम 1982 की अधिसूचना के आधार पर राज्य अधिनियम पर हावी है जो स्पष्ट रूप से शैक्षणिक संस्थानों को और विस्तार से, ऐसे संस्थानों में कर्मचारियों को भविष्य निधि का लाभ केंद्रीय अधिनियम के दायरे में लाता है। दूसरा, किसी प्रतिष्ठान को केंद्रीय

अधिनियम के दायरे से केवल तभी बाहर रखा जा सकता है जब वह राज्य या केंद्र सरकार के नियंत्रण में हो और उसके कर्मचारी सी. पी. एफ./पेंशन लाभों के हकदार हों। भले ही यह स्वीकार किया जाता है कि अपीलकर्ता राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित है, तथ्य यह है कि अपीलकर्ता के 16 अंशकालिक कर्मचारी राज्य नियमों के नियम 20 के आधार पर सी. पी. एफ./पेंशन लाभों के हकदार नहीं थे, जो स्पष्ट रूप से उन्हें ऐसे लाभ प्राप्त करने से बाहर करता है। मान लीजिए, विचाराधीन कर्मचारी अंशकालिक कर्मचारी हैं। अपीलार्थी द्वारा अपने पक्ष में जिस नियम पर भरोसा किया गया है, वह वास्तव में उसके खिलाफ जाता है। इस प्रकार, अपीलार्थी के स्कूलों को केंद्रीय अधिनियम के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता है।

10. श्री विजय प्रकाश तब प्रस्तुत करेंगे कि केंद्रीय अधिनियम किसी प्रतिष्ठान के अंशकालिक और पूर्णकालिक कर्मचारियों के बीच अंतर नहीं करता है। ऐसे प्रतिष्ठान के एक कर्मचारी को केंद्रीय अधिनियम के अनुसार एक कर्मचारी की परिभाषा में फिट होना चाहिए न कि किसी अन्य अधिनियम के अनुसार। अपीलार्थी का यह तर्क कि उसके अंशकालिक कर्मचारी हैं, जो अपने भविष्य निधि की कटौती के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, कोई आधार नहीं रखेगा क्योंकि केंद्रीय अधिनियम ऐसे तथाकथित अंशकालिक कर्मचारियों और नियमित कर्मचारियों के बीच कोई अंतर नहीं करता है।

11. श्री विजय प्रकाश प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी का रुख, कि वह अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि लाभ देने के लिए तैयार था, लेकिन राज्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिबंधित किया गया था, योग्यता के बिना है। राज्य शिक्षा अधिकारी केवल सी. पी. एफ. योजना से संबंधित है, ई. पी. एफ. योजना से नहीं। मान लीजिए, सी. पी. एफ. अपीलार्थी के अंशकालिक कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है, और इस प्रकार राज्य शिक्षा अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को अपने अंशकालिक कर्मचारियों के वेतन से ई. पी. एफ. में कटौती करने से रोकने का कोई सवाल ही नहीं है। वास्तव में, उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय में स्पष्ट रूप से दर्ज किया है कि अपीलार्थी को उचित उपायों का सहारा लेकर राज्य शिक्षा अधिकारी के साथ इस मुद्दे को हल करने के लिए कदम उठाने चाहिए थे, जो वह करने में विफल रहा है।

12. महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री कुणाल चीमा ने प्रस्तुत किया कि राज्य नियमों का नियम 20 अंशकालिक कर्मचारियों पर तब तक लागू नहीं होता है जब तक कि वे एक ही प्रबंधन द्वारा संचालित एक से अधिक स्कूलों में काम नहीं करते हैं और उन स्कूलों में पूर्णकालिक काम कर रहे हैं। यदि कोई स्कूल पूरी तरह से सहायता प्राप्त है और यदि नियम 20 ऐसे अंशकालिक कर्मचारियों पर

लागू होता है, तो ही राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना के अनुसार भविष्य निधि में कटौती की जाएगी।

13. श्री चीमा तब प्रस्तुत करते हैं कि 31 अक्टूबर, 2005 के सरकारी प्रस्ताव No.CCPS-1005/126/SER-4 के अनुसार, सरकार ने 1 नवंबर, 2005 को या उसके बाद भर्ती किए गए सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू मौजूदा पेंशन योजना को बदलने के लिए 'परिभाषित योगदान पेंशन योजना' नामक एक नई योजना शुरू की है। प्रस्ताव के अनुसार, सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया है कि वर्तमान पेंशन योजना और मौजूदा सामान्य भविष्य निधि योजना राज्य सरकार में 1 नवंबर, 2005 को या उसके बाद भर्ती किए गए सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।

14. श्री चीमा अंततः प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी के 16 अंशकालिक कर्मचारियों के संबंध में, उक्त कर्मचारियों को अंशकालिक कर्मचारी होने के कारण स्थायी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, राज्य सरकार ऐसे कर्मचारियों के भविष्य निधि बकाया में कटौती/भुगतान नहीं कर सकती क्योंकि वे स्थायी कर्मचारी नहीं हैं।

15. संबंधित पक्षों के वकील द्वारा प्रस्तुत दलीलों को सुनने के बाद, हम संबंधित अधिनियम की प्रयोज्यता के मुद्दे पर स्पष्टता प्राप्त करने के लिए केंद्रीय अधिनियम और राज्य अधिनियम के प्रावधानों के उद्देश्य और

परस्पर क्रिया की जांच करना आवश्यक समझते हैं। सबसे पहले, हम केंद्रीय अधिनियम का विज्ञापन कर सकते हैं। केंद्रीय अधिनियम की धारा 1 में निर्दिष्ट प्रतिष्ठानों पर उक्त अधिनियम के लागू होने को स्पष्ट किया गया है। वह इस प्रकार है:

"1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और अनुप्रयोग-

(1) इस अधिनियम को कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 कहा जा सकता है।

(2) यह जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में फैला हुआ है।

(3) धारा 16 में निहित प्रावधानों के अधीन रहते हुए, यह

(क) अनुसूची 1 में निर्दिष्ट किसी भी उद्योग में लगे हुए प्रत्येक कारखाने और जिसमें बीस या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं, और

(ख) ऐसे प्रतिष्ठानों के बीस या अधिक व्यक्तियों या वर्ग को नियुक्त करने वाले किसी अन्य प्रतिष्ठान पर लागू होता है, जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है

"बशर्ते कि केंद्र सरकार, ऐसा करने के अपने इरादे की कम से कम दो महीने की सूचना देने के बाद, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों को किसी ऐसे प्रतिष्ठान पर लागू कर सकती है जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किए गए [बीस] से कम व्यक्तियों को नियुक्त करता है।

(4) इस धारा की उप-धारा (3) या धारा 16 की उप-धारा (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जहां केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त को यह प्रतीत होता है कि नियोक्ता और किसी भी प्रतिष्ठान के संबंध में अधिकांश कर्मचारी इस बात पर सहमत हैं कि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रतिष्ठान पर लागू किया जाना चाहिए, वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को उस समझौते की तारीख से या उस समझौते में निर्दिष्ट किसी भी बाद की तारीख से उस प्रतिष्ठान पर लागू कर सकता है।

(5) जिस प्रतिष्ठान पर यह अधिनियम लागू होता है, वह इस अधिनियम द्वारा शासित होता रहेगा, भले ही उसमें किसी भी समय नियोजित व्यक्तियों की संख्या बीस से कम हो।

(ज़ोर दिया गया)

16. इस प्रावधान को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि केंद्रीय अधिनियम उसमें निर्दिष्ट प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी का प्रतिष्ठान धारा 1 (3) के उपखंड (बी) में निर्दिष्ट "अन्य प्रतिष्ठान" के दायरे में आ सकता है। यह निर्विवाद है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (3) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अधिसूचना प्रकाशित की है जिसमें सभी शैक्षणिक संस्थानों को "किसी भी अन्य प्रतिष्ठान" की श्रेणी में शामिल किया गया है, अर्थात्; विश्वविद्यालय; महाविद्यालय (चाहे वह विश्वविद्यालय से संबद्ध हो या न हो); विद्यालय (चाहे वह केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो या सहायता प्राप्त हो); कोई भी वैज्ञानिक संस्थान; कोई भी संस्थान जिसमें किसी भी मामले के संबंध में शोध किया जाता है; और कोई भी अन्य संस्थान जिसमें ज्ञान या प्रशिक्षण प्रदान करने की गतिविधि व्यवस्थित रूप से की जाती है।

17. उपरोक्त अधिसूचना के साथ केंद्रीय अधिनियम की धारा 1 के संयुक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि केंद्रीय अधिनियम उस अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के अधीन सभी कॉलेजों और स्कूलों पर लागू होगा।

18. इसके बाद सवाल यह उठता है कि क्या अपीलकर्ता स्कूल केंद्रीय अधिनियम की धारा 16 में निर्दिष्ट किसी भी अपवादात्मक श्रेणी के

अंतर्गत आता है। अपीलार्थी ने केंद्रीय अधिनियम की धारा 16 (1) के खंड (ए) के साथ-साथ खंड (बी) को लागू किया है। जहां तक खंड (ए) पर आधारित तर्क का संबंध है, यह इस आधार पर आगे बढ़ता है कि अपीलार्थी के स्कूल (जिसमें 16 अंशकालिक कर्मचारी काम कर रहे थे) ने पचास से कम व्यक्तियों को नियुक्त किया था और बिना शक्ति की सहायता के काम कर रहा था। हमारी राय में यह तर्क अपीलार्थी की सहायता के लिए नहीं आ सकता है। चूंकि, अपीलार्थी 29 स्कूल/कॉलेज चला रहा है और उसने लगभग 1151 स्थायी कर्मचारियों को नियुक्त किया है। केंद्रीय अधिनियम की धारा 2 ए वर्णन करती है कि जहां किसी प्रतिष्ठान में अलग-अलग विभाग होते हैं या उनकी शाखाएं होती हैं, चाहे वे एक ही स्थान पर स्थित हों या अलग-अलग स्थानों पर, ऐसे सभी विभागों या शाखाओं को एक ही प्रतिष्ठान का हिस्सा माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, यह तथ्य कि अपीलार्थी ने 50 से कम स्थायी कर्मचारियों को नियुक्त किया है और जो उस स्कूल में पावर की सहायता के बिना काम कर रहे हैं जिसमें 16 अंशकालिक कर्मचारी भी काम कर रहे थे, इस मामले को आगे नहीं ले जाएगा। हम पाते हैं कि अपीलार्थी ने न तो भौतिक तथ्यों का अनुरोध किया है और न ही कोई सबूत पेश किया है, ताकि केंद्रीय अधिनियम की धारा 2 ए में निर्धारित इस धारणा का खंडन किया जा सके कि अपीलार्थी द्वारा संचालित सभी स्कूल और कॉलेज एक ही प्रतिष्ठान का हिस्सा थे। यह तथ्य कि अपीलार्थी स्वयं राज्य सहकारी समिति

अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति है, अपीलार्थी को केंद्रीय अधिनियम के आवेदन से मुक्त नहीं करेगा।

19. हालाँकि, यह तथ्य कि अपीलार्थी धारा 16 (1) के खंड (ए) के दायरे में नहीं आता है, अपीलार्थी के लिए धारा 16 (1) के खंड (बी) पर भरोसा करके छूट के संबंध में तर्क पर विचार करने में कोई बाधा नहीं हो सकती है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि धारा 16 में निर्दिष्ट अपवादात्मक श्रेणियां पारस्परिक रूप से अनन्य हैं। उन्हें "या" शब्द से अलग किया जाता है। धारा 16 (1) का उपखंड (बी) एक स्वतंत्र अपवादात्मक श्रेणी है। यह केंद्र सरकार या राज्य सरकार से संबंधित या उसके नियंत्रण वाले किसी भी अन्य प्रतिष्ठान की ओर आकर्षित होता है और जिसके कर्मचारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाई गई किसी भी योजना या नियम के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि या वृद्धावस्था पेंशन के लाभों के हकदार हैं। केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों से छूट की मांग करने वाले संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा इन दो शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी के संबंधित स्कूलों/कॉलेजों में काम करने वाले कर्मचारी पात्रता के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाई गई अंशदायी भविष्य निधि योजना के दायरे में आते हैं। इस प्रकार केंद्रीय अधिनियम के तहत छूट प्राप्त करने के लिए आवश्यक दूसरी शर्त पूरी हो जाती है।

20. सवाल यह है कि जिन स्कूलों में 16 अंशकालिक कर्मचारी काम कर रहे थे, क्या उन्हें केंद्र सरकार या राज्य सरकार से संबंधित या उसके नियंत्रण में एक प्रतिष्ठान कहा जा सकता है। यह सवाल अब रेज़ इंटीग्रा नहीं है। इस न्यायालय ने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बनाम सनातन धर्म बालिका माध्यमिक विद्यालय और अन्य के मामले में इसी तरह के तर्क पर विचार किया है। पैराग्राफ 29 से 35 में, न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में इस मुद्दे का विश्लेषण किया:

"29. प्रत्यर्थी के इस तर्क के संबंध में कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार से संबंधित या उसके नियंत्रण में प्रतिष्ठान, यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रतिष्ठान या तो (ए) केंद्र सरकार या राज्य सरकार से संबंधित या (बी) केंद्र सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण में होने चाहिए। हमारे विचार में, उक्त खंड में उपयोग किए गए दो शब्दों के अलग-अलग अर्थ हैं। "संबंधित" शब्द स्वामित्व को दर्शाते हैं अर्थात् सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं को उक्त भाग के तहत शामिल किया जाएगा और "नियंत्रण में" शब्द स्वामित्व के अलावा अन्य नियंत्रण को दर्शाते हैं क्योंकि स्वामित्व पहले से ही "संबंधित" शब्दों के तहत शामिल किया जा चुका है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि दोनों शब्द "अन्य" शब्द से अलग हैं और इसलिए ये दोनों शब्द संस्थानों की दो पारस्परिक रूप से विशिष्ट श्रेणियों को संदर्भित करते हैं। जबकि केंद्र या राज्य सरकार से संबंधित संस्थान

राज्य के नियंत्रण को दर्शाते हैं, लेकिन निजी स्वामित्व वाले संस्थान विभिन्न तरीकों से सरकार के नियंत्रण में हो सकते हैं।

30. राज्य अधिनियम के तहत, राज्य द्वारा "नियंत्रण" निम्नलिखित तरीकों से है:

(ए) राज्य अधिनियम की धारा 3 के तहत, राज्य सरकार "गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थानों" को मान्यता प्रदान करती है।

यह प्रस्तुत किया गया था कि एक शैक्षणिक संस्थान को चलाने और संचालित करने के लिए राज्य द्वारा मान्यता का प्रमुख महत्व है: मान्यता देने के नियमों और शर्तों का पालन करने में संस्थान की विफलता पर उक्त मान्यता को वापस लिया जा सकता है।

(ख) राज्य अधिनियम की धारा 7 के तहत, राज्य सरकार केवल मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को सहायता प्रदान करती है। राज्य द्वारा दी गई सहायता का उपयोग केवल उस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है जिसके लिए सहायता दी गई है। धारा 8 के तहत, संस्थानों को राज्य द्वारा निर्धारित तरीके से खाते रखने की आवश्यकता होती है। यह प्रस्तुत किया गया था कि इस तरह से राज्य संस्थानों पर वित्तीय नियंत्रण रखता है।

(ग) धारा 9 के तहत, यह निर्धारित किया गया है कि संस्थान एक प्रबंध समिति द्वारा शासित होंगे और अधिनियम की धारा 10 राज्य को प्रबंधन अपने हाथ में लेने का अधिकार देती है यदि संस्थान "जब भी राज्य को यह प्रतीत होता है कि प्रबंधन समिति ने अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा या उसके तहत उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने में लापरवाही की है।

(घ) अधिनियम का अध्याय 5 संस्थानों की संपत्तियों और उस तरीके से संबंधित है जिसमें संस्थान संस्था की संपत्तियों का प्रबंधन कर सकते हैं। यह प्रस्तुत किया गया था कि अधिनियम की धारा 13 के तहत, संस्थानों को संस्थान के प्रबंधन को स्थानांतरित करने से पहले उक्त अधिनियम के तहत स्थापित सक्षम प्राधिकारी से आवेदन करना होगा और अनुमोदन प्राप्त करना होगा। धारा 15 के तहत, संस्थानों की अचल संपत्तियों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(ङ) अधिनियम की धारा 14 सक्षम प्राधिकारी को लिखित सूचना दिए बिना किसी भी संस्थान या उसके वर्ग या उसमें किसी भी विषय के शिक्षण को बंद करने पर प्रतिबंध लगाती है। यह प्रस्तुत किया गया था कि इस प्रकार संस्थान पर सरकार का कार्यात्मक नियंत्रण है।

(जे) राज्य अधिनियम का अध्याय VI कर्मचारियों की भर्ती और निष्कासन आदि से संबंधित है। उनका वेतन, सेवा की शर्तें, भविष्य निधि,

आचार संहिता सभी अधिनियम के तहत निर्धारित हैं। अधिनियम उन विवादों के समाधान के लिए एक न्यायाधिकरण की स्थापना का भी प्रावधान करता है जिसका निर्णय अंतिम और पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है।

31. राज्य सरकार संस्थान पर प्रशासनिक नियंत्रण भी रखती है। धारा 17 भर्ती के तरीके से संबंधित है और धारा 18 उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा कर्मचारियों को हटाया जा सकता है या बर्खास्त किया जा सकता है या रैंक में कम किया जा सकता है। धारा 28 राज्य सरकार को कर्मचारियों की आचार संहिता निर्धारित करने की अनुमति देती है और धारा 29 संस्थानों को अपने कर्मचारियों को वेतनमान और राज्य सरकार की समान श्रेणियों को दिए जाने वाले भतों से कम वेतन नहीं देने का आदेश देती है।

32. हमारे विचार में, राज्य अधिनियम शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में अपने आप में एक पूर्ण संहिता है और राज्य सरकार संस्थानों पर पर्याप्त नियंत्रण रखती है, भले ही संस्थान उसके स्वामित्व में न हों। "नियंत्रण" शब्द को ई. पी. एफ. अधिनियम, 1952 के तहत परिभाषित नहीं किया गया है।

33. हालाँकि, इस न्यायालय ने शामराव विट्ठल कूप बैंक लिमिटेड बनाम कासरगोड पांडुरंग माल्या, एस. सी. सी. ने पी. 604, पैरा 6 में

अनुमोदन के साथ "नियंत्रण" शब्द का अर्थ उद्धृत किया है जैसा कि शब्द और वाक्यांश, खंड 9, स्थायी संस्करण के पी. 442 में दिखाई देता है निम्नानुसार है:

'नियंत्रण' शब्द अधीक्षण, प्रबंधन या निर्देशन, प्रतिबंध या विनियमन के अधिकार का पर्याय है।

34. मैसूर राज्य बनाम अल्लम करिबसप्पा, एस. सी. सी. में पृष्ठ 501, पैरा 16 में इस न्यायालय ने "नियंत्रण" शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया: "नियंत्रण" शब्द नियंत्रण, संयम या प्रभाव का सुझाव देता है। नियंत्रण का उद्देश्य कार्रवाई से नियंत्रण और संयम रखना है।

35. हम आगे देखते हैं कि राज्य सरकार के पास शैक्षणिक संस्थानों के कामकाज को निर्देशित करने, प्रतिबंधित करने या विनियमित करने के लिए अधीक्षण या प्राधिकरण की शक्ति है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि संस्थानों ने ऊपर उल्लिखित शर्तों (1) और (2) दोनों को संतुष्ट किया है और इस प्रकार वे ई. पी. एफ. अधिनियम, 1952 की धारा 16 (1) (बी) के तहत निहित अपवाद के अंतर्गत आते हैं।

21. सवाल यह है कि क्या विषय राज्य अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में समान प्रावधान हैं, ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि राज्य सरकार अपीलार्थी जैसे प्रतिष्ठानों पर पर्याप्त नियंत्रण रखती

है। राज्य अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का विश्लेषण करने पर सनातन धर्म (उपरोक्त) के मामले में भी ऐसा ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। वर्तमान मामले में, राज्य अधिनियम, जिसे 16 मार्च, 1978 को भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है, में कई प्रावधान हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि राज्य सरकार का निजी स्कूलों पर किस हद तक नियंत्रण है:

क) राज्य अधिनियम की धारा 2 (19), 2 (20) और धारा 2 (21) इस तथ्य का संकेत हैं कि राज्य सरकार राज्य में प्राथमिक विद्यालयों और निजी विद्यालयों को मान्यता देती है।

ख) राज्य अधिनियम की धारा 4 (4) अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकार को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर संबंधित विद्यालय को दी गई मान्यता को वापस लेने का अधिकार देती है।

ग) राज्य अधिनियम की धारा 4 के तहत, राज्य सरकार को कर्मचारियों की सेवा के नियमों और शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियम बनाने की भी शक्ति है, जिसमें भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता और उसका पालन करने की प्रक्रिया, कर्तव्य, वेतन, भत्ते, सेवानिवृत्ति और अन्य लाभ, निजी स्कूलों के कर्मचारियों की सेवा की अन्य शर्तें और पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त संख्या में पदों के आरक्षण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य

प्राधिकरणों को लगातार निगरानी करने का अधिकार है कि स्कूल का प्रबंधन अपने कर्मचारियों की सेवा के निर्धारित नियमों और शर्तों को पूरा कर रहा है और उस उद्देश्य के लिए प्रबंधन को निर्देश जारी करना भी शामिल है।

घ) राज्य अधिनियम की धारा 4ए के तहत, निदेशक शिक्षा को कर्मचारियों के खिलाफ कथित कदाचार, दुर्यवहार या कर्मचारी की नैतिक अधमता के संबंध में पूछताछ के संबंध में निर्देश जारी करने का अधिकार दिया गया है।

ड) धारा 5 निजी स्कूलों के प्रबंधन के दायित्वों को स्वीकार करती है जैसे कि किसी निजी स्कूल में स्थायी रिक्ति को उस तरीके से भरना, जैसा कि सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

च) राज्य अधिनियम की धारा 16 के तहत, राज्य सरकार को निजी स्कूलों के कर्मचारियों के कर्तव्यों को नियंत्रित करने वाले नियम बनाने और उनकी संहिता के बारे में निर्देश जारी करने का अधिकार है। यह प्रशासनिक नियंत्रण का एक रूप है।

छ) राज्य नियम कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित मामलों और प्रबंधन द्वारा इसका पालन करने के तरीके से संबंधित हैं, जिसके संबंध में प्रबंधन राज्य के सक्षम प्राधिकरण को अनुपालन की रिपोर्ट करने के लिए

जवाबदेह हैं और उस संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना भी शामिल है।

ज) नियम विशेष रूप से पूर्णकालिक आधार पर या अंशकालिक आधार पर काम करने वाले लेकिन पूर्णकालिक काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी के लिए पेंशन भविष्य निधि और अन्य मामलों की सुविधा से भी संबंधित हैं।

झ) राज्य अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अलावा, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त और अनुदान सहायता प्राप्त करने वाले स्कूलों को अतिरिक्त शर्तों को पूरा करना होगा, जैसा कि अनुदान सहायता योजना और ऐसे स्कूलों के लिए लागू महाराष्ट्र माध्यमिक विद्यालय संहिता में निर्दिष्ट हैं। चूँकि सहायता अनुदान का उपयोग स्कूल द्वारा केवल उस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है जिसके लिए इसे दिया गया है और यह कि स्कूल को राज्य द्वारा निर्धारित तरीके से उचित खाते बनाए रखने और जमा करने की आवश्यकता है, ऐसे स्कूलों/कॉलेजों पर राज्य के वित्तीय नियंत्रण का भी संकेत है।

ट) माध्यमिक विद्यालय संहिता के प्रावधान राज्य सरकार को संस्थान के प्रबंधन को संभालने या स्थानांतरित करने का भी अधिकार देते हैं।

ठ) इसके अलावा राज्य प्राधिकरणों को यह देखना होगा कि प्रबंधन निर्दिष्ट के अनुसार उचित वेतन और भत्तों का भुगतान कर रहा है।

ड) माध्यमिक विद्यालय संहिता, जो कार्यकारी निर्देशों और आदेशों का एक संग्रह है, विद्यालयों की मान्यता, संगठन और प्रबंधन से संबंधित मामलों से भी संबंधित है; कर्मचारी सेवा की स्थिति, रिकॉर्ड और निरीक्षण; स्कूलों और छात्रावासों के रिकॉर्ड, रजिस्टर और निरीक्षण; और सहायता अनुदान आदि। सहायता अनुदान से संबंधित प्रावधान वेतन/गैर-वेतन अनुदान, भवन अनुदान और अन्य अनुदानों के मामलों से संबंधित हैं। इन मामलों के संबंध में प्रतिबंध ऐसे संस्थानों पर राज्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वित्तीय नियंत्रण का संकेत हैं। इसी तरह, अध्याय III कर्मचारियों की सेवा शर्तों, अभिलेखों और निरीक्षण से संबंधित है जो पर्याप्त कर्मचारियों के रखरखाव से संबंधित मामलों के लिए प्रदान करता है; कर्मचारियों की सेवा की शर्तें; और अनुशासन और छुट्टी के नियम। ये प्रावधान संस्थानों पर राज्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रशासनिक नियंत्रण का भी संकेत देते हैं। यह सब राज्य के भीतर कोई भी स्कूल शुरू करने से पहले या उस मामले के लिए अतिरिक्त अनुभाग शुरू करने और छात्रों की प्रवेश क्षमता बढ़ाने से पहले राज्य से मान्यता प्राप्त करने की प्रारंभिक आवश्यकता के अलावा है।

22. यह देखने के लिए पर्याप्त है कि राज्य अधिनियम, उसके तहत बनाए गए नियम और माध्यमिक विद्यालय संहिता के प्रावधान शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में अपने आप में एक पूर्ण संहिता हैं और ऐसे संस्थानों पर राज्य सरकार द्वारा ठोस नियंत्रण के प्रयोग की सीमा का संकेत देते हैं, चाहे वे उसके स्वामित्व में हों। राज्य सरकार के पास शिक्षण संस्थानों के कामकाज को निर्देशित करने, प्रतिबंधित करने या विनियमित करने की अधीक्षण और अधिकार है। यह अनिवार्य रूप से इस बात का अनुसरण करता है कि अपीलार्थी की स्थापना, जो इस मामले में अनुदान सहायता स्कूल है जिसमें 16 अंशकालिक कर्मचारी काम कर रहे थे, राज्य सरकार के नियंत्रण में है और इस प्रकार केंद्रीय अधिनियम की धारा 16 (1) (बी) की पहली शर्त को भी पूरा करेगा।

23. जैसा कि हमने अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी की स्थापना धारा 16 (1) (बी) में निर्दिष्ट दोहरी शर्तों को पूरा करती है, इसका पालन करना चाहिए कि उसे केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने से छूट दी गई है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, संबंधित प्राधिकरण और न्यायाधिकरण द्वारा यह पाया गया है कि अपीलार्थी के प्रतिष्ठान में काम करने वाले 16 अंशकालिक कर्मचारी प्रतिष्ठान के अन्य स्थायी कर्मचारियों पर लागू राज्य सी. पी. एफ. योजना के दायरे में नहीं थे। चूंकि, नियम 20 में स्कूल में काम करने वाले अंशकालिक कर्मचारियों को शामिल नहीं किया

गया है, यदि वे पूर्णकालिक काम का बोझ नहीं उठा रहे हैं। यह सच है कि तथ्य के उक्त निष्कर्ष को पलट नहीं दिया जा सकता है। फिर भी, क्या न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए प्राधिकरण के निर्णय को बरकरार रखना संभव है-कि अपीलकर्ता अपने अंशकालिक कर्मचारियों के संबंध में केंद्रीय अधिनियम के तहत भविष्य निधि के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है? उस दिशा में आंतरिक बात यह है कि केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों को अपीलार्थी की स्थापना के खिलाफ लागू किया जाता है। यह अस्वीकार्य है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, केंद्रीय अधिनियम की धारा 16 यह स्पष्ट करती है कि केंद्रीय अधिनियम के प्रावधान प्रतिष्ठान पर लागू नहीं होंगे, यदि वे उसमें प्रदान की गई अपवादात्मक श्रेणी में से किसी एक के अंतर्गत आते हैं। विशेष रूप से, यह छूट समग्र रूप से प्रतिष्ठान के लिए और सभी उद्देश्यों के लिए, केंद्रीय अधिनियम के लागू होने से है। एक बार जब प्रतिष्ठान को छूट प्राप्त करने के लिए धारा 1.6 में निर्दिष्ट अपवाद श्रेणी द्वारा कवर किया जाता है, तो यह समझ से परे है कि केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों को ऐसे प्रतिष्ठान के खिलाफ इस तर्क पर लागू किया जा सकता है कि कुछ (इस मामले में 16) अंशकालिक कर्मचारी राज्य सरकार की सी. पी. एफ. योजना के दायरे में नहीं थे, जैसा कि इसके बाकी कर्मचारियों पर लागू होता है।

24. ऐसी स्थिति को स्वीकार करना संभव नहीं है कि भले ही प्रतिष्ठान को केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने से छूट प्राप्त हो, फिर भी उसके कुछ (16) अंशकालिक कर्मचारियों के संबंध में कार्रवाई की जानी चाहिए। यह एक असंगत दृष्टिकोण की ओर ले जाएगा, जिसकी परिकल्पना केंद्रीय अधिनियम द्वारा नहीं की गई है। किसी भी अन्य दृष्टिकोण को अपनाने के परिणामस्वरूप केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों को फिर से लिखा जाएगा जिसका अर्थ यह होगा कि यद्यपि प्रतिष्ठान को केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने से छूट दी गई है, फिर भी कुछ स्थितियों में केंद्रीय प्राधिकरणों के लिए ऐसे प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार होगा। हमारी राय में, एक बार जब प्रतिष्ठान केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों के आवेदन की छूट के लिए योग्य हो जाता है, तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि केंद्रीय अधिनियम के तहत अधिकारी उस पर अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं या प्रतिष्ठान को केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए कह सकते हैं, जब तक कि प्रतिष्ठान की छूट को वापस नहीं लिया जाता है या न्यायिक रूप से हटा नहीं दिया जाता है। केंद्रीय अधिनियम की धारा 16 में कर्मचारियों के संबंध में केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की आंशिक छूट की अवधारणा की परिकल्पना नहीं की गई है, लेकिन यह छूट सभी उद्देश्यों के लिए प्रतिष्ठान को संचालित करती है।

25. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता 29 स्कूल/कॉलेज चला रहा है और 28 स्कूलों/कॉलेजों के संबंध में राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहा है। अपीलार्थी के उक्त विद्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को राज्य सरकार की अनुमति और अनुमोदन से नियुक्त किया गया है और वे राज्य सी. पी. एफ. योजना द्वारा शासित हैं। राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया की सख्ती से निगरानी की गई है। इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ता अपने कर्मचारियों के वेतन बिल शिक्षा विभाग को जमा कर रहा है जो ऐसे कर्मचारियों के वेतन को सीधे उनके बैंक खातों में जमा करता है। प्रासंगिक समय पर, अपीलार्थी ने लगभग 1151 कर्मचारियों को नियुक्त किया था जो निजी स्कूलों के कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाई गई अंशदायी भविष्य निधि योजना के दायरे में थे (16 अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर जो पूर्णकालिक काम नहीं कर रहे थे)। अपीलार्थी ने राज्य सरकार की अनुमति और अनुमोदन से उन 16 अंशकालिक कर्मचारियों को नियुक्त किया था। यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि राज्य सरकार इस तथ्य से पूरी तरह से अवगत थी कि वे अंशकालिक कर्मचारी राज्य की सी. पी. एफ. योजना के लाभों के हकदार नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में, अपीलार्थी के कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या, यदि उनमें से सभी नहीं हैं, तो लगभग 1151 कर्मचारी, राज्य अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित निजी स्कूलों पर लागू राज्य सरकार की अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा कवर किए

गए थे। सिर्फ इसलिए कि अपीलार्थी के स्कूल में काम करने वाले 16 अंशकालिक कर्मचारी राज्य सी. पी. एफ. योजना के लाभों के लिए पात्र नहीं थे, केंद्रीय अधिनियम की धारा 16 के तहत अधिग्रहित अपीलार्थी की स्थापना की छूट की स्थिति बंद नहीं होगी या स्वचालित रूप से वापस नहीं ली जाएगी।

26. एक बार जब कोई प्रतिष्ठान केंद्रीय अधिनियम की धारा 16 के तहत किसी भी अपवाद श्रेणी के तहत आता है, तो केंद्रीय अधिनियम द्वारा सशक्त अधिकारियों को ऐसे प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं होगा; और विशेष रूप से इस आधार पर कि प्रतिष्ठान में काम करने वाले कर्मचारियों (16 अंशकालिक कर्मचारी) की एक छोटी संख्या प्रतिष्ठान के बाकी नियमित कर्मचारियों को नियंत्रित करने वाली राज्य अंशदायी भविष्य निधि योजना के तहत लाभों के लिए पात्र नहीं थी।

27. यह कहने के बाद, हमें यह मानना चाहिए कि अपीलार्थी की स्थापना के खिलाफ प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधिकारी (ओं) द्वारा वसूली की कार्रवाई शुरू करना, जिसे अन्यथा केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने से छूट दी गई थी, पूरी तरह से कानून के अधिकार के बिना है। अपीलार्थी ने न्यायाधिकरण के समक्ष सनातन धर्म (उपरोक्त) के मामले पर भरोसा रखा था। लेकिन न तो न्यायाधिकरण और न ही उच्च न्यायालय ने इस पर विचार किया है। हालाँकि, न्यायाधिकरण ने द

शामराव विट्ठल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम कासरगोड पांडुरंग माल्या के मामले में निर्णय पर भरोसा करने का फैसला किया। । सनातन धर्म (उपरोक्त) के मामले में इस निर्णय पर विधिवत विचार किया गया है और इसे अलग किया गया है, जैसा कि रिपोर्ट किए गए निर्णय के पैराग्राफ 33 से देखा जा सकता है।

28. चाहे जो भी हो, अब तक जिन कारणों का उल्लेख किया गया है, हमें इस अपील को स्वीकार करने और उच्च न्यायालय के निर्णय को दरकिनारा करने में कोई संकोच नहीं है; और केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों को लागू करके अपीलार्थी द्वारा संचालित संबंधित स्कूल के खिलाफ वसूली शुरू करने के लिए केंद्रीय अधिनियम के तहत अधिकारियों की पूरी कार्रवाई, जिसका कोई आवेदन नहीं था।

29. तदनुसार, उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति दी जाती है, जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होता है।

देविका गुजराल

अपील को मंजूरी दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक कैलाश पूनिया द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।